हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 130 देहरादून, बुधवार, 09 नवंबर, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

महंगाई भत्ते पर 3 लाख कर्मचारी व पेंशनरों को खुशखबरी का इंतजार 3

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 8 नवम्बर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों, आन्दोलनकारियों एवं देश के लिये सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हाल ही में प्रदेश में आई आपदा में जान गवाने वाले लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट की है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के साथ औद्योगिक उत्तराखण्ड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल विहारी वाजपेई को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखण्ड तथा उत्तराखण्डवासियों से आत्मिक लगाव है, आज केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम में विकास कार्य संचालित किये जा रहे हैं। हमारे चारधाम, न सिर्फ हमारी आस्था और श्रद्धा के केन्द्र हैं बल्कि हमारी आर्थिकी की बुनियाद भी है। इस वर्ष लगभग 45 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम और हेमकुण्ड साहिब के दर्शन के लिए आए। कोरोना काल से पूर्व की तुलना में यह संख्या 35 प्रतिशत अधिक है।प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में मल्टी मॉडल कनेक्टीवीटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। इसका प्रभाव आने वाले समय में प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के रूप में दिखेगा। प्रदेश में सड़कों के निर्माण में तेजी से कार्य हो रहा है, इसके लिये केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का पूरा सहयोग मिल रहा है। रूद्रपुर एवं रामपुर मुरादाबाद बायपास के निर्माण से प्रदेश के कुमांऊ क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। और टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे पर केन्द्र सरकार द्वारा सहमति दी जा चुकी है। आज एयर कनेक्टीवीटी के क्षेत्र में भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अक्टूबर को प्रदेश के सीमान्त गांव माणा में राज्य के स्थानीय उत्पादों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा स्थलों के भ्रमण पर जितना व्यय करते हैं उसका कम से कम 5 प्रतिशत व्यय वहां के स्थानीय उत्पादों के क्रय करने पर व्यय करें। हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष करोड़ों लोग पर्यटन एवं तीर्थाटन पर आते हैं। उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले स्थानीय उत्पादों से हमारे लोगों की आर्थिकी मजबूत होने के साथ ही देश व दुनिया में इसकी पहचान भी बनेगी। उन्होंने कहा कि रानीबाग (नैनीताल) स्थित एच.एम.टी. की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखण्ड को प्राप्त होना प्रदेश के लिये डबल इंजन सरकार की एक और बड़ी सौगात है। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी तथा हमारे युवा रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे

उत्तराखण्ड के युवा हमारा भविष्य हैं। इसीलिए हमने युवाओं साथ धोखा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। भर्तियों में घोटाला करने वालों पर कड़ी क़ानूनी कारवाई की जा रही है। पारदर्शिता और समयबद्धता से परीक्षाओं के आयोजन के लिये हमने उत्तराखण्ड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेण्डर के अनुसार 7 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।

हमारी सरकार द्वारा राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति लाई गई है। साथ ही "मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना" में 08 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रूपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरूआत करने में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में है। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रूपये वार्षिक तक के निशुल्क ईलाज की सुविधा दी जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सेवा, सुशासन, संवेदनशीलता और गरीब कल्याण के मंत्र पर चल रही है।

ब्लॉक स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर जन समस्याओं की सुनवाई हो रही है। समस्याओं के त्वरित निवारण पर बल दिया जा रहा है। लोगों को योजनाओं का सही लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र के आधार पर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 लांच किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि ही नहीं, वीरभूमि भी है और सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान हमारा कर्तव्य है। इसको ध्यान में रखते हुए देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना पर तेजी से काम किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में भी वृद्धि की गई है। हम हिम प्रहरी योजना पर भी काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती जिलों में बसने के लिये सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह वाक्य कि "21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा"। प्रधानमंत्री का हम पर यह विश्वास हर उत्तराखण्डवासी का सम्मान है। जहाँ इस बात से एक ओर हमें अपने राज्य पर गर्व होता है, तो दूसरी ओर बड़ी जिम्मेदारियों का भी अहसास होता है। हमारी सरकार ने राज्य को 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प का मूलमंत्र अपनाया है।

राज्य स्थापना दिवस की बधाई : अजय भट्ट

देहरादून , 8 नवम्बर। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है । भट्ट ने राज्य की स्थापना के संघर्ष के लिए शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों व राज्य संघर्ष में दिन-रात जुटे राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया है।केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने 22 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है 22 वर्ष पहले जब राज्य अलग हुआ था तो राज्य आंदोलनकारियों के अनुरूप सरकारों ने धीरे-धीरे काम करना शुरू किया आज सड़क, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया गया है। भट्ट ने कहा कि आज राज्य के पास अपने मेडिकल कॉलेज, अपना एम्स, चारधाम कनेक्टिविटी, भारत माला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग और आखरी पर्वतीय गांव में रोड कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के समन्वय से उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है उन्होंने कहा कि राज्य के इस विकास में राज्य के प्रत्येक नागरिक का योगदान है और भट्ट ने अपेक्षा की कि भविष्य में भी राज्य के बेहतर और समग्र विकास के लिए आम जनमानस के साथ मिलकर सरकार प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अजय भट्ट ने पुनः राज्य के निर्माण के संघर्ष के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया है तथा राज्य आंदोलन के संघर्ष में साथी रहे राज्य आंदोलनकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनायें : सतपाल महाराज

देहरादून, 8 नवम्बर। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण, सिंचाई, जलागम, धर्मस्व, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं।कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 9 नवंबर, 2000 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही पृथक राज्य की मांग को जनभावनाओं के अनुरूप पूर्ण किया गया। उसके पश्चात प्रदेश को संवारने और विकसित करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है।मंत्री महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास का जो भी काम हुआ है, वह इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी, दोनों यहां के काम आ रहे हैं। उन्होने राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनायें देते हुए कहा कि प्रकृति की गोद में बसा यह राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे ऐसी हम कामना करते हैं।

राज्य की समृद्धि, खुशहाली एवं उन्नति की कामना : ऋतु खंडूड़ी भूषण

देहरादून , 8 नवम्बर । उत्तराखंड राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की समृद्धि, खुशहाली एवं उन्नति की कामना की है।

विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों व आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए राज्य स्थापना दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। ऋतु खंडूड़ी ने अपने संदेश में कहा है कि तमाम संघर्षों, शहादतों एवं अत्याचार झेलने के बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के लिये समर्पित शहीद आंदोलनकारियों तथा जन सामान्य के सपनों का राज्य विकसित करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। उत्तराखंड की पहचान देश-दुनिया में देवभूमि एवं सैनिकों की भूमि के रूप में है। हमें इस पहचान को बनाए रखना है। यहां सहज, सरल, शांतिप्रिय लोग प्रदेश की ताकत भी हैं और पहचान भी, उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति पर नाज है।नए प्रगतिशील भारत में उत्तराखंड बढ़-चढ़कर अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सम्मानित जीवन जीने का अधिकार होता है। इन्हीं अधिकारों के सपनों को लेकर अलग उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया गया था। अगर हम सभी ईमानदारी से कोशिश करें तो अवश्य ही एक ऐसा उत्तराखंड बनाने में सफल होंगे जहां सभी क्षेत्रों की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, सभी को आगे बढ़ने के तमाम अवसर और साधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमेशा शहीदों का ऋणी रहेगा।राज्य आन्दोलन के शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य बनाए। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना होगा विशेष कर युवाओं को कि अपने प्रदेश की विशेष पहचान बनाए रखने की दिशा में कार्य करेंगे और प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए सद्भाव से एकजुट होकर प्रयास करेंगे।

Happy Birthday Uttarakhand : मैं उत्तराखंड बोल रहा हूँ

राज्य स्थापना दिवस विशेष

मो० सलीम सैफ़ी
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आज जिस देवभूमि के 22 वें जन्मोत्सव का हम और आप जश्न मना रहे हैं वो उत्तराखंड नब्बे के दशक में हुए जन आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ था । ऐसा आंदोलन, जिसमें गोदी के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग लोगों की भागीदारी थी। कई परिवार तो ऐसे थे, जिनकी तीन-तीन पीढियां सक्रिय थीं।आंदोलन के दौरान आए दिन बंद और चक्काजाम का ऐलान होता था। बंद का मतलब बंद होता था। हर मोहल्ले और इलाकों की महिलाएं युवा और बच्चे अपने क्षेत्र के सभी सरकारी दफ्तरों को बंद करवाते और पहाड़ की सशक्त महिलाएं समूह में मुठियाँ ताने निकलती थीं।

उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था. लेकिन इसके पीछे पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलकारियों को मुजफ्फरनगर तिराहा गोली कांड के रूप में एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी. हालांकि अगर हम उत्तरांचल के विभाजन के कारणों की बात करें तो इसके बहुत ही सहज कारण निकलकर सामने आते हैं. दरअसल सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टी से उस समय संयुक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर्वतीय क्षेत्र से काफी दूर पड़ती थी. उस समय पहाड़ के लोगों का कहना था कि उनके क्षेत्र से देश की राजधानी पास है लेकिन प्रदेश की राजधानी पहुंचने के लिये उनको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी.

उत्तरप्रदेश से विभाजन का मुख्य कारण यहां के लोगों की पहाड़ी पहचान थी. उत्तरप्रदेश अपनी विशालता की वजह से उत्तराखंड की पहचान के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था. वह उनकी भाषा (कुमाऊं और गढ़वाली), उनकी संस्कृति, उनके साहित्य, उनके इतिहास और उनके लोगों की बात को और समस्याओं को सुन ही नहीं पा रहा था. जिससे वहां की जनता में असंतोष के स्वर फूटने लगे थे और उन्होंने अपने और अपने लोगों के लिये एक पहाड़ी राज्य की मांग काफी तेज कर दी थी.लेकिन हर बार उत्तर प्रदेश पहाड़ की इस मांग को राजनीतिक उपेक्षा की वजह सिरे से खारिज कर देता था.

क्या है रामपुर तिराहा गोलीकांड ?

यह पूरा घटना क्रम 1 अक्टूबर, 1994 की रात से जुड़ा है, जब आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से अलग पहाड़ी प्रदेश की मांग कर रहे थे. आंदोलनकारी इस बात को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे थे. प्रदेश के अलग-अलग पर्वतीय क्षेत्र से लोग 24 बसों में सवार हो कर 1 अक्टूबर को रवाना हो गये.लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन्हें रामपुर तिराहे पर रोकने की योजना बनाई और पूरे इलाके को सील कर आंदोलनकारियों को रोक दिया. पुलिस ने आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर में रोक दिया लेकिन आंदोलकारी लगातार दिल्ली जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

पुलिस पर लगा था प्रदर्शनकारी महिलाओं के रेप का आरोप

इस दौरान पुलिस की आंदोलनकारियों से नोकझोंक शुरू हो गई. जानकारों और प्रत्यक्षदर्शियों के विभिन्न मीडिया संस्थानों को दिये गये इंटरव्यु के अनुसार राज्य आंदोलनकारियों ने सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी तो अचानक वहां पर पथराव शुरू हो गया. इस पथराव में तात्कालीन मुजफ्फरनगर के डीएम अनंत कुमार सिंह घायल हो गए.इसके बाद यूपी पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं. उन्होंने आंदोलनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और लगभग ढाई सौ से ज्यादा राज्य आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया. लेकिन इन सब के घटनाओं के बीच यूपी पुलिस पर शर्मसार कर देने वाले कुछ आरोप लगे जिनका मुकदमा कई वर्षों तक चलता रहा. दरअसल प्रदर्शनकारियों के साथ रात में झड़प के दौरान यूपी पुलिस पर आंदोलनकारी महिलाओं के रेप का आरोप लगा.

स्थानीय गांव वाले बने थे सहायक

हालांकि रात में जब आंदोलनकारियों पर यह बर्बरता हो रही थी तो उस रात स्थानीय गावों के लोग महिलाओं को शरण देने के लिए आगे भी आए थे. अगले दिन समाचार पत्रों से पता चल है कि उस दिन पुलिस की गोली से देहरादून निवासी रविंद्र रावत, भालावाला निवासी सतेंद्र चौहान, बदरीपुर निवासी गिरीश भदरी, जबपुर निवासी राजेश लखेड़ा, ऋषिकेश निवासी सूर्यप्रकाश थपलियाल, ऊखीमठ निवासी अशोक कुमार और भानियावाला निवासी राजेश नेगी शहीद हुए थे.देर रात लगभग पौने तीन बजे जब 42 बसों में सवार होकर राज्य आंदोलनकारी रामपुर तिराहे पर पहुंचे तो पुलिस और राज्य आंदोलनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई. इस दौरान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने 24 राउंड फायरिंग की थी. जिसमें सात आंदोलनकारियों की जान चली गई और 17 राज्य आंदोलनकारी बुरी तरह घायल हो गये.

रामपुर तिराहा कांड के बाद आंदोलन ने पकड़ी गति

रामपुर तिराहा हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाये जाने की मांग ने और जोर पकड़ लिया क्योंकि मुजफ्फरनगर में हुई बर्बरता के बाद राज्य आंदोलनकारियों और प्रदेश के लोगों में गुस्सा भड़क गया था. नए राज्य की मांग को लेकर प्रदेश में धरना और विरोध प्रदर्शन का दौर चलने लगा. आंदोलन की आग में युवाओं, बुजुर्गों के साथ-साथ स्कूली बच्चे भी इस आग में कूद पड़े. आखिरकार 6 साल तक चले आंदोलन, धरना प्रदर्शन के बाद 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य उतरांचल बनाने की स्वीकृति दे दी गई थी. वहीं 21 दिसंबर 2006 को यूपी से विभाजित हुए इस राज्य 'उतरांचल' का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था.

धामी सरकार ने दिखाया है 2025 का विजन

अनेकों मिथकों को पीछे छोड़ते हुए मौजूदा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता के सामने विजन 2025 रखा है जिसमें उन्होने रजत जयंती वर्ष तक उत्तराखंड को सर्वोत्तम राज्य बनाने की शपथ ली है। उन्नति , विकास , स्वास्थ्य , शिक्षा , नशामुक्त और अपराध मुक्त राज्य बनाने की दिशा में कड़े , बड़े और चौकाने वाले फैसले भी लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि शहीदों के सपनों का पहाड़ 2025 की 9 नवम्बर की सुबह तक एक नए मुकाम पर नज़र आएगा।

राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने की तैयारी में उत्तराखंड

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 8 नवम्बर। उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए संशोधित विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस माह होने वाली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार ने आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के लिए विधेयक मंजूर किया था, लेकिन तब से यह राजभवन में लंबित था।पिछले माह मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने संशोधन के लिए इसे वापस मंगा लिया था। सूत्रों ने बताया कि कार्मिक विभाग ने इस पर न्याय विभाग से परामर्श मांग लिया है। अब संशोधित विधेयक के रूप में इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है, जिससे इसी विधानसभा के सत्र में इसे पारित कराकर राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा जा सके।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संशोधित विधेयक कैबिनेट में लाने के संकेत दिए हैं। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। विधेयक को लेकर तैयारी भी की जा रही है।

क्या था मामला : हाईकोर्ट ने अगस्त, 2013 में आंदोलनकारियों के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। 2018 में इसके जीओ, सरकुलर व अधिसूचना को खारिज कर इसे असंवैधानिक करार दिया था। एनडी सरकार ने 2004 में आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया था। इसके तहत सात दिन से अधिक जेल में रहने वाले और घायलों को डीएम के स्तर से सीधे नौकरी।छह दिन तक जेल में रहने वालों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। अगस्त, 2010 में निशंक सरकार ने चिह्नित आंदोलनकारियों को और दिसंबर, 2011 में खंडूड़ी सरकार ने आश्रितों को भी आरक्षण की व्यवस्था की थी।

महंगाई भत्ते पर 3 लाख कर्मचारी व पेंशनरों को खुशखबरी का इंतजार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 8 नवम्बर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते (डीए) की फाइल पर अपना अनुमोदन दे दिया है। राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारी व पेंशनरों की डीए पर नजर लगी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में डीए देने की घोषणा की थी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने फाइल पर अनुमोदन मिलने की पुष्टि की है।बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने पर सहमति हो गई थी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। माना जा रहा था कि राज्य स्थापना दिवस के आसपास मुख्यमंत्री डीए की सौगात दे सकते हैं।शनिवार को उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा

कर दी थी। सोमवार को उन्होंने डीए की फाइल पर अनुमोदन दे दिया। अनुमोदन की फाइल अब प्रक्रिया में है आज डीए का आदेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। पैसे का इंतजाम हुआवित्त विभाग ने महंगाई भत्ते पर खर्च होने वाली धनराशि की व्यवस्था कर ली है। डीए पर हर माह 42 से 45 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। चार फीसदी डीए मिलने से राज्य कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के हिसाब से 550 से लेकर 10 हजार रुपये तक की वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।

सीईओ स्मार्ट सिटी लिमिटेड सोनिका ने परेड ग्राउंड निर्माण कार्यों का लिया जायज़ा

देहरादून , 8 नवम्बर। देहरादून की डीएम और स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस सोनिका ने परेड ग्राउंड पहुँच कर निर्माण कार्यों की रफ़्तार देखी। निरीक्षण के समय देहरादून स्मार्ट सिटी के अधिकारी एवं ठेकेदार, फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पौधारोपण, बाउंड्री वॉल निर्माण, फुटपाथ निर्माण, कार पार्किंग जोन विकास कार्य आदि का जायजा लिया गया। सीईओ सोनिका ने कार्य में आवश्यक रिसोर्स एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए है। अधिकारियों/अभियंताओं को कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करवाने एवं कार्यों की समय सीमा निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह निर्देश दिए गए की किए गए कार्यों को समय पर सभा समाप्त किए जाने के साथ-साथ कार्यों की गुणवत्ता पर भी विशेष

ध्यान रखा जाए । मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने देहरादून स्मार्ट सिटी के अधिकारियों एक एवं कार्यदायी एजेंसी एवं नोडल अधिकारियों को समय सीमा का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि परेड ग्राउंड रिजूवनेशन कार्य देहरादून स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है तथा यह शहर के बीचो-बीच स्थित है इसलिए इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए।

कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल शबद कीर्तन, गुरुवाणी और लंगर में हुए शामिल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ऋषिकेश 8 नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरु नानक देव जयंती पर 553 साला महान प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल शबद कीर्तन, गुरुवाणी और लंगर के कार्यक्रम हुए। श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में कैबिनेट मंत्री डॉ अग्रवाल पहुंचे। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका।

इस मौके पर सिख समाज की ओर से मंत्री डॉ अग्रवाल को सरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मंत्री डॉ अग्रवाल ने रागी जत्थों द्वारा गुरुवाणी और शबद कीर्तन का पाठ किया गया। इस मौके पर मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि 553 साल पहले भारत में गुरु नानक देव जी नामक एक महान संत हुए। गुरु नानक देव जी ने बगदाद तक

आध्यात्मिकता, परमेश्वर के साथ एकता, और भक्ति के महत्व को फैलाया था। आज, सिख समुदाय गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाता है और सिख समुदाय के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। गुरु नानक देव जी ने सांसारिक मामलों में उलझने पर लोगों को अपने अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने लोगों को हमेशा परमेश्वर के नाम को न भूलने का आवाहन किया। गुरु नानक का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ था।डॉ अग्रवाल ने गुरु नानक देव की जयंती

पर माया में न उलझने की अपील की। साथ ही सदैव धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने का आह्वान किया।इस मौके पर गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार गोविंद सिंह, उपाध्यक्ष प्रेम सिंह, बूटा सिंह, परमजीत डंग, इंद्रपाल सिंह, भारत भूषण रावल, पार्षद अजीत गोल्डी, शिव कुमार गौतम, तनु तेवतिया, संजीव पाल, कपिल गुप्ता, पंकज गुप्ता, शैलेन्द्र बिष्ट, राजेश धींगरा, गुरु वचन सिंह, इंद्र कुमार गोदवानी, मण्डल अध्यक्ष दिनेश सती, मोहन सिंह जस्सल, हिम्मत सिंह, गुरमेल सिंह आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

एक ही लक्ष्य - एक ही सपना
सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखण्ड अपना

राज्य स्थापना दिवस

9 नवम्बर

की हार्दिक शुभकामनाएं

"21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हरसंभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

संकल्प नये उत्तराखण्ड का

- प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरुप श्री केदारनाथ व श्री बदरीनाथ धाम का पुनर्निर्माण व पुनर्विकास। इस वर्ष रिकार्ड 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किये।
- कुमाऊं के पौराणिक मन्दिरों के लिये मानसखण्ड मन्दिर माला की कार्ययोजना।
- होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती।
- चारधाम ऑल वेदर रोड से राहें हुई आसान। टनकपुर-पिथौरागढ़ भी शामिल।
- केंद्र सरकार से पौंटा साहिब-देहरादून, बनबसा-कंचनपुर, भानियावाला-ऋषिकेश, काठगोदाम-लालकुंआ-हल्द्वानी बाईपास और रुद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सौगात।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से कार्य गतिमान, टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेललाइन के सर्वे पर सहमति।
- पर्वतीय क्षेत्रों में रोप-वे हेतु पर्वतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री जी द्वारा गौरीकुण्ड - केदारनाथ और गोविंदघाट - हेमकुण्ड साहिब रोप-वे का शिलान्यास।
- दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों में 1202 मोबाइल टावर की स्वीकृति।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांवों का शत प्रतिशत विद्युतिकरण।
- देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना पर तेजी से काम, राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि।
- रानीबाग (हल्द्वानी) स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन केन्द्र से उत्तराखण्ड को हस्तांतरित।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 9 लाख 38 हजार किसानों के खातों में लगभग 1767 करोड़ की राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है।
- किसानों को तीन लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के पांच लाख रुपए तक का ऋण।
- कोविड काल से दो साल में 600 से अधिक नये उद्योगों की स्थापना, 35 हजार करोड़ से अधिक का निवेश, 90 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार।
- वोकल फॉर लोकल के लिये एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू।
- समान नागरिक संहिता पर बढ़े कदम, समिति द्वारा ड्राफ्ट पर मंथन।
- भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064, सभी शिकायतों पर गम्भीरता से एक्शन।
- उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि में वृद्धि। आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी।
- स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत।
- मुख्यमंत्री बालाश्रय योजनाः आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा।
- आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपये वार्षिक तक के निःशुल्क ईलाज की सुविधा।
- ऊधमसिंहनगर में एम्स का सैटेलाईट सेंटर की केंद्र से सहमति।
- राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से 7 हजार पदों पर पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। जल्द 19 हजार पदों पर भी शुरु की जाएगी भर्ती।
- "मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना" में 08 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति।

"माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक कहा है। हम प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरुप राज्य को हर क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं।"

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी
www.uttarainformation.gov.in uttarakhandDIPR DIPR_UK uttarakhand DIPR

73 वर्ष की उम्र में पहाड़ के रामकृष्ण ने 5000 मीटर दौड़ में जीता सोना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 8 नवम्बर। उत्तराखंड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की 5000 मीटर दौड़ में बड़कोट निवासी 73 वर्षीय रामकृष्ण बडोनी ने जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीता है।

क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाई दीइतनी उम्र में भी बडोनी के जज्बे और उनकी इस जीत पर क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी अपने जज्बे को बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीतने की शुभकामनाएं दी हैं।सेना से सेवानिवृत्त हैं रामकृष्ण बडोनीउत्तरकाशी जिले के बड़कोट निवासी 73 वर्षीय रामकृष्ण बडोनी सेना से सेवानिवृत्त हैं।

उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी दिनचर्या नियमित रखी हुई है। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के 5000 मीटर दौड़ में स्वर्णपदक जीतने के बाद अब रामकृष्ण बडोनी आगामी फरवरी में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।इससे पहले भी रामकृष्ण बडोनी प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ में पदक जीत चुके हैं।

आगे भी दिनचर्या को नियमित बनाए रखने का प्रयासस्वर्ण पदक जीतने पर एथलीट रामकृष्ण बडोनी का कहना है कि वह सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद से अपनी दिनचर्या पूर्व की भांति नियमित रखे हुए हैं और आगे भी दिनचर्या को नियमित बनाए रखने का प्रयास है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीतने का प्रयासएथलीट रामकृष्ण बडोनी ने कहा कि राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीतने का उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। कहा कि वह उम्र की बाधाओं को तोड़कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग करना चाहते हैं।

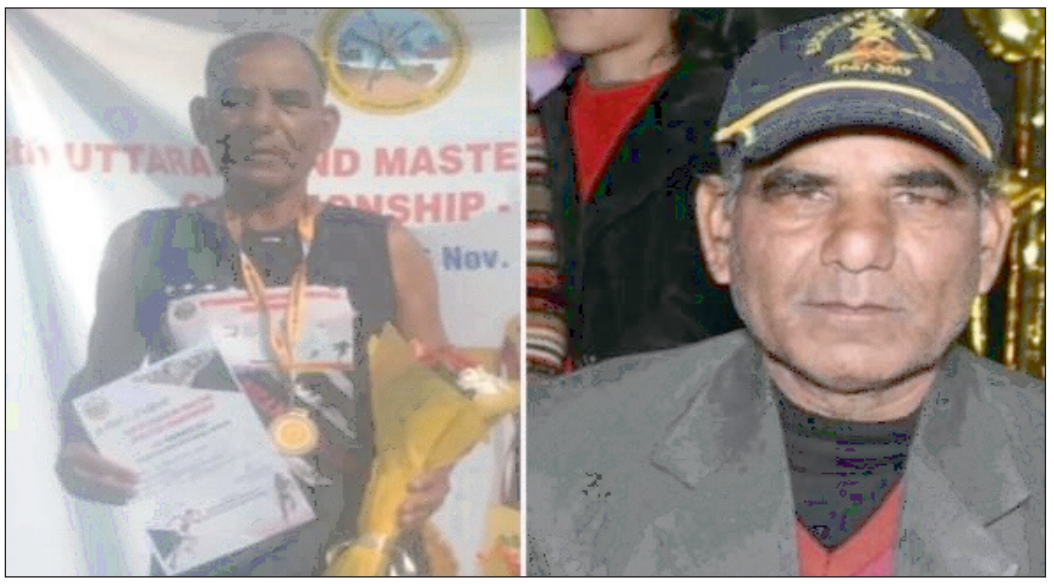

शहीद दुर्गामल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी, मंत्री गणेश जोशी का गोरखाली सुधार सभा ने जताया आभार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 8 नवम्बर। देहरादून में गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष एवम् पदाधिकारियो ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया है। दरअसल 25 अगस्त 2022 को गढ़ी कैंट में शहीद दुर्गा मल्ल के 78वें श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति की ओर से शहीद दुर्गा मल्ला पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमे मुख्य अतिथि के तौर पर काबीना मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की थी। जिसमे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष एवम् पदाधिकारियों ने मंत्री जोशी से शहीद दुर्गामल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करने की बात कही थी।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय पर पत्र लिखकर जानकारी साझा की और शहीद दुर्गामल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया। जिसके बाद अब भारत सरकार ने शहीद दुर्गामल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया है। जिसके लिए गोरखाली सुधार सभा के सभी पदाधिकारियों ने मंत्री गणेश जोशी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि शहीद दुर्गामल्ल के नाम डाल टिकट जारी होने से उनके परिवार में भी काफी खुश नजर आ रहा है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गोरखा स्वतंत्रता सेनानी शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज में शामिल होकर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था । यंहा तक कि उन्होंने अंग्रेंजी हुकूमत से मिले सभी प्रलोभनों को भी ठुकरा कर देश प्रेम को ही सर्वोपरि रखा था। मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा सैनिकों के सम्मान ओर उनके कल्याण के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है।

इस अवसर पर गोरखली सुधार सभा के अध्यक्ष पीएस थापा, नेपाली भाषा समिति के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, इंजी मेग बहादुर थापा, महासचिव श्याम राणा, राजन छेत्री, पूजा सुभा चंद, प्रभा शाह, बी.के. बरल आदि उपस्थित रहे।

यहाँ निभाई जाती है दूल्हे की जूते से पिटाई की अजीबोगरीब रिवाज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 नवंबर । भारत में शादी के दौरान जूता चुराई की रस्म होती है, ये तो आप जानते ही होंगे, जबकि स्कॉटलैंड में दुल्हन की सहन शक्ति की कई तरह से परीक्षा ली जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां शादी के दौरान दूल्हे की पिटाई वाली रस्म की जाती है ? आप सोच रहे होंगे ये कैसा रिवाज़ भला .... लेकिन अजीब रस्मों से भरी इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दुनिया में हर जगह पर शादी से जुड़ी अलग-अलग प्रकार की रस्में होती हैं.

जैसे भारत में शादी के दौरान जूता चुराई की रस्म होती है, तो वहीं स्कॉटलैंड में दुल्हन की सहन शक्ति की कई तरह से परीक्षा ली जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां शादी के दौरान दूल्हे की पिटाई वाली रस्म की जाती है? चलिए जानते हैं इस अजीबोगरीब रस्म के बारे में... दरअसल, साउथ कोरिया में शादी के दौरान दूल्हे को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मार खानी पड़ती है.

यह ऐसी रस्म है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है.यहां दूल्हे को लकड़ी से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है और उसके तलवों पर डंडे मारे जाते हैं. इतना ही नहीं, इस दौरान दूल्हे की जूते से भी पिटाई होती है... इस अजीबोगरीब रिवाज के पीछे की वजह के बारे में लोगों का मानना है कि जो दूल्हे इस रिवाज में पास हो जाते हैं, उन्हें आगे जीवन में कभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही इतनी मार खा लेते हैं कि पूरी जिंदगी मजबूत बने रहते हैं.ऐसा कहा जाता है कि दूल्हे के दोस्त ही दूल्हे को उल्टा लटका देते हैं और फिर सभी दोस्त मिलकर उसके तलवों पर डंडे मारते हैं. दक्षिण कोरिया में इस रिवाज को बड़े उत्साह से मनाया जाता है.

क्या आप जानते हैं कैसे काम करती है टच स्क्रीन ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 नवम्बर । आप और हम सभी लोग ज्यादातर टच स्क्रीन वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. यहां तक कि अब मार्केट में टच स्क्रीन लैपटॉप भी आने लगे हैं.

अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से हम टच स्क्रीन फोन या लैपटॉप यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये टच स्क्रीन फोन कैसे काम करते हैं? कैसे हम सिर्फ उंगलियां को स्क्रीन से टच करके ही इन्हे कंट्रोल करते हैं? कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आया तो जरूर होगा, लेकिन शायद बहुत कम को इस सवाल का जवाब मालूम होगा. आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके फोन की टच स्क्रीन काम कैसे करती है और इसके क्या फायदे हैं?

दरअसल, टच स्क्रीन एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होती है, जिस पर हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके या इसे केवल टच करके कंट्रोल कर सकते हैं. आइए इसके विज्ञान के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कैसे काम करता है टच स्क्रीन?

दरअसल, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के नीचे एक Electrically Conductive Layer मौजूद होती है. जब हम स्क्रीन को टच करते हैं तो डिस्प्ले थोड़ा बेंड होता है और इससे टच स्क्रीन को काम करने में मदद मिलती है. हम जैसे ही फोन की स्क्रीन पर उंगलियों से टच करते हैं , वैसे ही स्क्रीन के नीचे Electric Current में एक बदलाव होता है. इस बदलाव से ही पता चलता है कि फोन पर कहां टच किया गया है. यह जानकारी प्रोसेसिंग के साथ कंट्रोलर को जाती है. ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से काम करता है कि जैसे ही हम स्क्रीन को टच करते हैं फोन तुरंत उसको रिस्पोंड कर देता है.

टच स्क्रीन के फायदे

टचस्क्रीन फोन को इस्तेमाल करने में बहुत आसान होते हैं. इन टचस्क्रीन मोबाइल फोन में किसी बटन की जरूरत नहीं होती है. बटन वाले फोन के बटन अक्सर कुछ सालों में टूट जाते हैं. बटन न होने के कारण स्क्रीन का साइज भी बड़ा नजर आता है. इसको कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है. टचस्क्रीन मोबाइल फोन में आप अपनी उंगली के प्रिंट का पासवर्ड भी लगा सकते हैं. इसका यह फायदा है कि कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना आपका फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.

संपादकीय

भारत-सऊदी संबंध

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की भावी यात्रा भारत और खाड़ी देशों के बीच गहरे होते संबंधों की कड़ी में अहम मोड़ साबित हो सकती है. उल्लेखनीय है कि भारत अगले महीने जी-20 समूह की अध्यक्षता संभालने जा रहा है तथा अगले साल इस समूह के देशों की शिखर बैठक भारत में होनी है. अभी विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना तथा सतत विकास के लिए प्रयास करना प्रमुख प्राथमिकताओं में है. ऊर्जा व्यापार में भारत और सऊदी अरब का साझा संबंध बहुत मजबूत है. भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आयात करता है तथा तेल एवं गैस का निर्यात सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और इस क्षेत्र में परस्पर सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं. यदि दुनिया वर्तमान दर से जीवाश्म ईंधनों का उपभोग जारी रखती है, तो इनके स्रोत आगामी चार-पांच दशकों में समाप्त हो जायेंगे. इसका दूसरा परिणाम यह होगा कि तब तक कार्बन उत्सर्जन इतना अधिक हो चुका होगा कि धरती का तापमान जीने लायक नहीं होगा तथा प्राकृतिक आपदाएं प्रलयकारी हो चुकी होंगी. अगर 2050 तक तापमान के स्तर को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल होता है, तो 80 फीसदी कोयला, 50 फीसदी गैस तथा 30 फीसदी तेल भंडार इस्तेमाल के लायक नहीं रहेंगे. भंडार कम होने लगेंगे, तो खनन भी बहुत महंगा होता जायेगा. ऐसे में महत्वपूर्ण उत्पादक और उपभोक्ता होने के नाते सऊदी अरब और भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर विश्व को ले जाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. भारत उन देशों में है, जो बहुत तेज गति से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहा है तथा इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है. बहुत समय से सऊदी सरकार इस संबंध में सहकार के लिए प्रयासरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने में लगा हुआ है, साथ ही भारत और फ्रांस की अगुवाई में सौ से अधिक देशों का सौर गठबंधन भी सक्रिय है. इन प्रयासों में सऊदी अरब महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है. भारत अपने व्यापक मानव संसाधन और तकनीकी अनुभवों से सऊदी अरब को उल्लेखनीय मदद मुहैया करा सकता है. वास्तव में, कई दशकों से बड़ी संख्या में भारतीय सऊदी अरब एवं अन्य खाड़ी देशों की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण आधार हैं. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश में अत्याधुनिक शहरों का निर्माण कर रहे हैं. उम्मीद है कि इस यात्रा से परस्पर सहयोग के नये युग का सूत्रपात होगा.

खेल के क्षेत्र में नये-नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे उत्तराखंड के खिलाडी : रेखा आर्य

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर 8 नवम्बर , उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभागान्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के रूद्रपुर में 3088.11 लाख की लागत से बनने वाले क्रीड़ा बहुउद्देशीय भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होने कहा कि इस क्रीड़ा बहुउद्देशीय भवन में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें बच्चे अभ्यास कर खेल के क्षेत्र में नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर अपने लिये सुनहरा भविष्य बनायेंगे।

उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना लागू की जिसके अन्तर्गत पूरे प्रदेश में लगभग 5 हजार बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि आज का समय पढ़ाई के साथ-2 खेल का भी है, यदि किसी बच्चे के भीतर किसी खेल के प्रति जज्बा, पसंद है तो वह उस खेल में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर के भी अपना सुनहरा भविष्य बना सकते है। उन्होने कहा कि खेल भी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा वह सब कुछ दे सकता है जो एक व्यक्ति का सपना होता है।

उन्होने कहा कि हमारी सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी सामान्य खिलाड़ियो के समान धनराशि, सुविधा मुहैया कराने का काम किया है। उन्होने कहा कि खेल के क्षेत्र में सरकार लगातार बेहतर कार्य कर रही है, हर खिलाड़ी को वह सारी सुविधा प्रदान की जायेगी जिससे वह अपने ग्राम, ब्लॉक, तहसील, जनपद, प्रदेश व देश का नाम रोशन करें। उन्होने कहा कि आज इस बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया जा रहा है बहुत जल्द इसका लोकार्पण भी किया जायेगा। उन्होने कार्यदायी संस्था को उच्चगुणवत्ता के साथ निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण करें। मा0 मंत्री ने बताया कि भविष्य में 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इसी बहुउद्देशीय भवन में किया जायेगा। उन्होने सभी खिलाड़ियों को अपने हुनर में धार लागने की बात कही। उन्होने कहा कि भविष्य में खिलाड़ियों को बहुत अवसर प्राप्त होने वाले है इसलिए सभी खिलाड़ी निरन्तर अभ्यास करते रहें और अपने हुनर को और निखारें।

सावधान ! फेसबुकिया महिलाओं को लूट रहे हैं 'हाइटेक ठग', क्या आप हैं सावधान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 नवम्बर , क्या आप फेसबुक यूजर हैं? क्या आपके मोबाइल में फेसबुक एप डाउनलोड है? क्या आप फेसबुक के जरिए अपने दोस्तों से कनेक्ट होते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर आपके दोस्तों, आपके परिवारवालों की सुरक्षा के लिए है। ये खबर उन लोगों के लिए है जो लोग किसी भी तरह से फेसबुक से जुड़े हुए हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप फेसबुक का इस्तेमाल न करें, लेकिन कुछ सावधानियां हैं वो आपको बरतनी होंगी, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स के की नज़र आजकल सबसे ज्यादा फेसबुक पर है। इन खतरनाक अपराधियों के पास कई ऐसे शातिर प्लान है जिसके जरिए ये लोग फेसबुक यूजर को अपने जाल में फंसा रहे हैं।

घटना नंबर 1

एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की और उसके पिता रोते-रोते मेरठ के पल्लवपुरम थाने पहुंचे और बताया अपना किस्सा कि कैसे फेसबुक के जरिए एक लड़के ने उन्हें लाखों का चूना लगा दिया। पढ़ी-लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की फेसबुक के ठग के झांसे में आ गई। करीब एक साल पहले फेसबुक के जरिए इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को एक शख्स ने फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी। इस शख्स ने खुद को डॉक्टर बताया। धीरे-धीरे दोनों की फेसबुक में दोस्ती बढ़ने लगी।खुद को डॉक्टर पॉल बताने वाले इस शख्स ने पीड़ित लड़की से फोन नंबर भी लिया। दोनों की फोन पर बातें होने लगी। ये शख्स विदेश के नंबर से फोन करता था, ये दिखाने के लिए कि ये विदेश में एक बड़ा डॉक्टर है। इसने पहले लड़की से दोस्ती कर उसका विश्वास जीता और उसके बाद एक बार लड़की पांच लाख रूपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। पैसे मांगने का ये सिलसिला चलता रहा है। धीरे-धीरे करके इस फेसबुक के इस ठग ने करीब 52 लाख रूपये की रकम इस लड़की से निकलवा ली।

इसके बाद अचानक उस लड़के के फोन आने बंद हो गए। फेसबुक से भी वो लड़का गायब हो गया। तब जाकर इस आईटी इंजीनियर लड़की की आंख खुली, लेकिन तब तक बैंक से 52 लाख रूपये जा चुके थे। लड़की को समझ आया कि वो फेसबुक ठगी के बड़े जाल का हिस्सा बनी है। परिवारवालों को लड़की ने पूरा मामला बताया, केस भी दर्ज किया गया, लेकिन अब तक ठग का कोई पता नहीं चल पाया है। इस परिवार के पास अब रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है।

घटना नंबर 2

चार महिलाओं ने मीडिया को बताया कि फेसबुक के ठग ने उनसे करोड़ों रूपये ठग लिए हैं। ये चारों महिलाएं एक ही शख्स की ठगी का शिकार बनी। इनमें से दो महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं जबकि दो आगरा की हैं। इन्होंने बताया कि मोहित नाम का एक शख्स फेसबुक में महिलाओं को दोस्ती की रिक्वेस्ट भेजता है। इस शख्स ने खुद को एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एचआर बताकर इन चारों महिलाओं से दोस्ती की। मोहित नाम के इस शख्स ने अपनी दर्द भरी कहानी बताकर इन महिलाओं को अपने झांसे में लिया और फिर इनसे लाखों रूपये ले लिए। इन चार महिलाओं से ये साइबर क्रिमिनल एक करोड़ से ज्यादा लूट चुका है। ये चारों एक दूसरे को नहीं जानती थीं, इस ठग की फेसबुक की फ्रेंडलिस्ट की जरिए इन महिलाओं की आपस में बात हुई और फिर सामने आई मोहित की ठगी। जैसे ही इन्हें इस साइबर क्रिमिनल के बारे में पता चला, इन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भी बताया।ज्यादातर मामलों में ये सामने आया है कि इन फेसबुक ठगों की शिकार अक्सर महिलाएं बनती हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने समस्त प्रदेश वासियों को दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

अपने सन्देश में उन्होंने कहा कि जिस उत्तराखंड का सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था. वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है. उत्तराखंड राज्य गठन के पीछे दो सदियों का संघर्ष है. कई राज्य आंदोलकारियों की शहादत है, जिसके बदौलत आज उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आया है, लेकिन अभी भी उनके सपनों का उत्तराखंड अधूरा है. राज्य की मूल अवधारणा के प्रश्न हमारे सामने आज भी वैसे ही खड़े है । वरिष्ठ राजनेता आर्य ने कई मुद्दों पर अपनी बात सामने रखते हुए ज्वलन्त मुद्दों को जनता और राज्य सरकार के सामने रखा है

१.उत्तराखंड में लगातार घट रही उत्पादकता और बढ़ रहे खर्च के बदौलत आज प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, जिसका सरकार अभी तक स्थाई समाधान नहीं ढूंढ पाई है. आज यह स्थिति है कि हर महीने सरकार को 200 से 300 करोड़ रुपये तक का ऋण बाजार से उठाना पड़ता है.

२. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक आज भी बनी है. आज भी उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ी-लिखी ग्रेजुएट बेटियां घास काटते और गांव में घर का काम करते नजर आती हैं. इसका मूल कारण महिलाओं के रोजगार को लेकर सरकार ने कोई बड़े कदम नहीं उठाए.

3. पहाड़ी इलाकों से पलायन राज्य का एक बड़ा नासूर बन चुका है. सरकार पलायन पर नकेल लगाने में नाकाम साबित हुई है,पलायन को लेकर राज्य में हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि कई गांव अब घोस्ट विलेज बन चुके हैं.

४. भाजपा सरकार की ग़ैरसैन, ग्रीष्मकालीन राजधानी केवल घोषणा और नाम तक ही सीमित रह गई है.

पर्वतीय जिले मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बीते दो दशक में १२०० से अधिक गांव वीरान हो चुके हैं। ४००० स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलीटेक्निक व आइटीआइ भी बंद करने जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में रोजाना कई लोग दम तोड़ रहे हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए पृथक राज्य की मांग की गई थी। पर स्थिति यह है कि राज्य का युवा रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। प्रदेश में रोजगार की पूरी व्यवस्था ठेकेदारों के आधीन है। कर्मचारियों का उत्पीडन हो रहा है। महिलाओं पर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राज्य के संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है।स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, बिजली प्रदेश को आज भी दूसरे प्रदेशो से बिजली लेनी पड़ रही है। जंगलो क़े हालत यह हैं कि हर साल आग लगना आम बात हो गई हैं, जिससे जल संकट बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उत्तराखंड की इस साल की सबसे बड़ी घटना उत्तराखंड परीक्षा घोटाला। यह एक ऐसी घटना है ,जिसने उत्तराखंड के विकास को खुली किताब की तरह सबके सामने रख दिया। हमारे सपनो के राज्य में माफिया दीमक की तरह कितने अंदर तक घुस चूका है ,इस घटना से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। उत्तराखंडियत को बचाए रखने के लिए पहाड़ की जनता के दुख दर्द को समझना अति आवश्यक है। प्रदेश में एक सख्त भू कानून लागू करने की आवश्यकता है और यह भू-कानून पूरे प्रदेश की 100% भूमि के लिए लागू होना चाहिए। पर्वतीय जिलों में सबसे बड़ी समस्या गुणवत्ता वाले स्कूलों की है और रोजगार सृजन के अवसरों के लिए राज्य स्तरीय कौशल निर्माण विश्विद्यालय की स्थापना की मांग अरसे हो रही है. राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है. उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मूलतः गांव ही विकास और लोगों की बसाहट की मूल इकाई हैं. गांवों की खुशहाली मजबूत करनी होगी जिससे पलायन रुके और स्थानीय लोगों को छोटे मोटे रोजगार की तलाश में गांव से पलायन न करना पड़े.

भारतीय महिलाओं में बढ़ी शराब की लत , तनाव और चिंता बनी वजह

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 नवम्बर , देश के सभी राज्यों में शराब की खपत तेजी से बढ़ रही है. एक सर्वे में बीते दिनों दिवाली से पहले तीन दिन की बिक्री के चौंकाने वाले आंकड़े सामने हैं. जिसमें सिर्फ 3 दिन में ही दिल्ली वालों ने 100 करोड़ से ज्यादा की शराब गटक ली. जिसमें महिलाओं में शराब की खपत तेजी के साथ बढ़ी है. उन्होंने साबित कर दिया Liquor पीने के मामले में महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं. महिलाओं के लिए इसका सबसे कारण शराब पर मिलने वाली छूट है. दिल्ली में कई दिनों तक एक बोतल की खरीद पर एक बोतल मुफ्त में दी जा रही थी.

शराब के सेवन की मात्रा में आई तेजी

आंकड़ों के अनुसार, 2022 में शराब का सेवन करने वाली महिलाओं पर हुए सीएडीडी दिल्ली सर्वेक्षण (CADD Delhi Survey) में हुआ है. इसमें 5,000 महिलाओं को शामिल किया गया था और जो निष्कर्ष सामने आए उनमें पाया गया कि महिलाओं में शराब के उपयोग में तेज बढ़ोतरी हुई है. इससे ये सामने आया है कि अब महिलाएं पहले से ज्यादा शराब पीने लगी हैं. सर्वे में शामिल 77 फीसदी से ज्यादा महिलाओं ने ये माना है कि दुकानों पर एक के साथ एक फ्री जैसी छूट ने शराब की खरीदारी को और अधिक आकर्षक बना दिया है.

ये रहा सबसे बड़ा कारण

सर्वे के मुताबिक, महिलाओं में शराब की अधिक खपत का सबसे बड़ा कारण तनाव और चिंता है. आंकड़ों को देखें तो 45.7 फीसदी महिलाओं में खपत बढ़ने की वजह तनाव (Tension) था. इसके अलावा 34.4 फीसदी ने कहा कि आसानी से शराब की उपलब्धता के चलते सेवन में वृद्धि हुई है. वहीं 30.1 फीसदी का कहना था कि विशेष रूप से बोरियत दूर करने के चक्कर में ज्यादा शराब का सेवन किया गया.

चिंताओं से निजात पाने के लिए किया सेवन

आंकड़ों से पता चला है कि कोरोना महामारी के दौरान से महिलाएं सामान्य से अधिक शराब पीने लगी हैं. महिलाएं अपनी चिंताओं से निजात पाने के लिए भी शराब का अधिक सेवन कर रही थीं. जो पुरुषों द्वारा अनुभव की जा रही चिंताओं के चलते शराब की खपत के अनुपात से अधिक था. CADD द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में COVID -19 महामारी के आगामी लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन, शराब की उपलब्धता और खपत में बढ़ोतरी, खर्च के पैटर्न, शराब पीने की आदतों समेत अन्य मानकों को आधार बनाया गया.

मेरठ के इस गाँव में बसी है फुटबॉल की दुनिया

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 नवम्बर , मेरठ में एक ऐसा गांव है,जो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में फुटबॉल खेला नहीं बनाया जाता है। खेती से आजीविका चलाने वालों ने फुटबॉल के जरिए बेरोजगारी को ऐसी किक मारी है, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। फुटबॉल निर्माण ने इस क्षेत्र को अलग ही पहचान दे दी है.... उत्तर प्रदेश के मेरठ का फुटबॉल इन दिनों काफी चर्चित हो रहा है। यहां का एक गांव फुटबॉल को लेकर खासा चर्चित हो रहा है। जी हां, आपने सही सुना फुटबॉल के लिए। भले ही देश में फुटबॉल का खेल अधिक चर्चित नहीं हो। क्रिकेट प्रेमी इस देश में आखिर फुटबॉल की चर्चा क्यों? तो आप जान लीजिए कि मेरठ का यह गांव फुटबॉल खेल नहीं, बल्कि गेंद बनाने को लेकर खासी चर्चा में आ गया है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के सिसौला बुजुर्ग गांव की। इस गांव के करीब 3000 परिवार जीविका के लिए फुटबॉल की सिलाई करते हैं। यहां पर हर साल कुल मिलाकर 11 लाख गेंदें बनती हैं। भले ही पश्चिमी यूपी के इस गांव के पास न तो फुटबॉल का मैदान है। न ही यहां से अब तक कोई महान खिलाड़ी निकला है। लेकिन, पिछले कुछ सालों में सिसौला बुजुर्ग फुटबॉल के खेल में जाना माना नाम बन चुका है।सिसौला बुजुर्ग में हर साल लाखों फुटबॉल बनते हैं। करीब तीन दशक पहले फुटबॉल बनाने की शुरुआत की गई थी। मेरठ में खेल का सामान बनाने का निर्माण करने वाली इकाई में काम करने वाले एक युवक हरि प्रकाश ने कुछ कच्चा माल घर लाया। साथियों को प्रेरित किया कि गांव में भी फुटबॉल का निर्माण किया जा सकता है। शौकिया तौर पर फुटबॉल बनाने का काम कुछ लोगों ने शुरू किया। उस समय उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने एक गरीब बस्ती में विकास की नींव रख दी है। शौकिया तौर पर शुरू किया गया काम में लोगों को मजा आने लगा। ऑर्डर दिए जाने लगे। बाजार मिलने लगा। फिर फुटबॉल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, बदस्तूर जारी है।

हर रोज तैयार होती है तीन हजार फुटबॉल

सिसौला बुजुर्ग औसतन प्रतिदिन 3000 फुटबॉल बनाता है, जिसमें प्रत्येक परिवार 5-6 गेंदों की सिलाई करता है। ग्राम प्रधान मोहम्मद राशिद ने कहा कि सालाना कारोबार 3 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से सालाना लगभग 11 लाख फुटबॉल का यहां निर्माण होता है। इस फुटबॉल निर्माण ने गांव की आबादी को अलग ही आकार दे दिया है। 63 साल के प्रकाश को गांव के बदलाव पर काफी गर्व है।

उनके बेटे आलोक ने उनसे पदभार संभाला है और हजारों को काम देने वाली कई छोटी इकाइयों में से एक चलाते हैं। वे कहते हैं कि पहले हम ज्यादातर अपने दम पर काम कराते थे। सरकारी योजनाओं के बावजूद, हम तक बहुत कुछ नहीं पहुंच पाता था। प्रकाश कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंटऔर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) से गांव को और मदद मिल सकती है।